



सा०/No. : 5-1(352)/2016-PD

दिनांक/Dated: 25.10.2021

प्रेषक / From : संयुक्त सचिव (प्रशासन)  
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान  
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित संकल्प को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Resolution issued by the Government of India for your information, guidance and compliance:

| क्रम सं.<br>Sl. No. | संकल्प सं.<br>Resolution No.   | विषय/<br>Subject   |
|---------------------|--|--|
| 1.                  | भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 05.10.2021 का संकल्प सं. 5(4)-बी(पी.डी.)/2021<br>Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Resolution No. 5(4)-B(PD)/2021 dated 05.10.2021 | जी.पी.एफ. और अन्य सामान निधियों के संशोधित ब्याज दर के संबंध में।<br>Revised interest rate of GPF and other similar funds – reg. |

भवदीय/Yours faithfully

  
25/10/21

संतोष कुमार/Santosh Kumar  
अनु.अधि.(नीति प्रभाग)/Section Officer (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

- आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ/  
Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.
- कार्यालय प्रति/Office copy.

(भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशनाथ)

एफ. संख्या 5(4)-बी(पी.डी.)/2021

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

(बजट प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 अक्टूबर, 2021

संकल्प

आम जनकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2021-2022 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिव्यक्तियों की कुल उमा रकमों पर दो जाने वाली खाज दर 1 अक्टूबर, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक 7.1% (सात दसमलब एक प्रतिशत) होगी। यह दर 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं:

1. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)।
2. अश्वघोषी भविष्य निधि (भारत)।
3. आखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
4. राज्य सेलेक्ट भविष्य निधि।
5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।
6. भारतीय आयुर्विभाग भविष्य निधि।
7. भारतीय आयुर्विभाग कास्खाना कामगार भविष्य निधि।
8. भारतीय नौसेना गोली कामगार भविष्य निधि।
9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
10. सशस्त्र सेना काविक भविष्य निधि।

2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।



(आशीष वच्चानी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक, (संकर्माधी शाखा)

भारत सरकार मुख्यालय,

मायापुरी, दिल्ली।

फा. संख्या 5(4)-बी(पी.डी.)/2021

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक सेवा सचिवालय, राज्य सेवा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, सच लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय, निवर्तमान आयोग और नैतिक आयोग को प्रति प्रेषित।

निम्नलिखित को भी प्रति प्रेषित:-

1. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और उनके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालय।
2. अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण।
3. महालेखा नियंत्रक (10 प्रतिभ्या)।
4. कार्मिक, लोक शिवालय और पेंशन मंत्रालय (पेंशन यूनिट/अखिल भारत सेवा प्रभाग)।
5. मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार (6 प्रतिभ्या)।
6. मंत्रालयों/विभागों के मुख्य नियंत्रक/लेखा नियंत्रक।
7. रक्षा लेखा महानियंत्रक।
8. सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त सचिव।
9. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के सचिव/उप-सचिव।
10. सचिव स्टाफ यूनिट, राष्ट्रीय जेसीएम परिषद।
11. सभी सदस्य स्टाफ यूनिट, राष्ट्रीय जेसीएम परिषद।
12. एनआईसी वेबपोर्टल हेतु।



(प्रवीण सिंह)

उप सचिव (बजट)

(TO BE PUBLISHED IN PART I SECTION 1 OF GAZETTE OF INDIA)

F.No. 5(4)-B(PD)/2021

Government of India

Ministry of Finance

Department of Economic Affairs

(Budget Division)

New Delhi, the 5 October, 2021

**RESOLUTION**

It is announced for general information that during the year 2021-2022, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.1% (Seven point one percent) w.e.f. 1st October, 2021 to 31st December, 2021. This rate will be in force w.e.f. 1st October, 2021. The funds concerned are:

1. The General Provident Fund (Central Services).
2. The Contributory Provident Fund (India).
3. The All India Services Provident Fund.
4. The State Railway Provident Fund.
5. The General Provident Fund (Defence Services).
6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
9. The Defence Services Officers Provident Fund.
10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.

2. Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.

To,

The Manager, (Technical Branch)  
Government of India Press, Mayapuri, Delhi.

F.No.5(4)-B(PD)/2021

Copy forwarded to all Ministries/Departments of Government of India, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Union Public Service Commission, Supreme Court, Election Commission and NITI Aayog.

Copy also forwarded to :-

1. Comptroller & Auditor General of India and all offices under his control.
2. Chairman, Pension Fund Regulatory and Development Authority.
3. Controller General of Accounts (10 copies).
4. Ministry of Personnel Public Grievances and Pension (Pension Unit/All India Services Division).
5. Financial Adviser of Ministries/Departments (6 copies).
6. Chief Controller of Accounts/Controller of Accounts of Ministries/Departments.
7. Controller General of Defence Accounts.
8. Finance Secretary of all State Governments and Union Territories.
9. Secretary to Governors/Lt. Governors of all States/Union Territories.
10. Secretary Staff Side, National Council of JCM.
11. All Members, Staff Side, National Council of JCM.
12. NIC - For uploading on webhost.



(Parveen Singh)

Under Secretary (Budget)